

दूध की तीन कंपनियों से सवा लाख को रोजगार



अच्छी खबर

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में तीन नये मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां स्थापित करने की घोषणा को मूर्त रूप देने का काम शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कंपनियां स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेज दिया जाएगा। इन तीनों कंपनियों के स्थापित हो जाने पर एक दर्जन जिलों की करीब सवा लाख ग्रामीण महिलाएं रोजगार से जुड़ जाएंगी।

एनडीडीबी डेरी सर्विसेज देगा कंपनियों को सहयोग

विभाग के मुताबिक एक कंपनी की स्थापना पर करीब 40 करोड़ रुपये तक खर्च किया जाएगा। इस धनराशि से दूध कलेक्शन सेंटर, कोल्ड चैन की स्थापना के साथ ही महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायक कंपनी एनडीडीबी डेरी सर्विसेज इन कंपनियों को तकनीकी सहयोग देगा। बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ते राज्य के दूसरे मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के प्रस्ताव को भारत सरकार की इंपावर्ड कमेटी ने सहमति दे दी है। तीन साल में इस प्रोजेक्ट पर करीब 43 करोड़ रुपये खर्च होंगे।



महिला सामर्थ्य योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। इस धनराशि से बलिनी की तर्ज पर तीन नई मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां बनाई जाएंगी। करीब 1.25 लाख ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा।

भानु चंद्र गोस्वामी, मिशन निदेशक,
उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

शासन ने महिला सामर्थ्य योजना के लिए 200 करोड़ रुपये बजट का प्राविधान किया गया है। तीन नई मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों के स्थापित हो जाने पर राज्य में इस तरह की पांच कंपनियां हो जाएंगी।

महिलाएं जुड़ेंगी डेरी वैल्यू चेन से: पहली कंपनी का कार्यक्षेत्र

गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर जिला होगा। दूसरी कंपनी का कार्यक्षेत्र रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी तथा तीसरी कंपनी का कार्यक्षेत्र बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर तथा रामपुर जिला होगा। गोरखपुर को आधार बनाकर स्थापित की जाने वाली

कंपनी से करीब 40 हजार ग्रामीण महिलाएं, सुल्तानपुर को आधार बनाकर स्थापित की जाने वाली कंपनी से करीब 35 हजार तथा बरेली-सीतापुर को आधार बनाकर स्थापित की जाने वाली प्रोड्यूसर कंपनी से 40 हजार से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा।